दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार, 10 मार्च 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 162

महत्वपूर्ण एवं खास

गया में नक्सलियों ने पोकलेन मशीन में लगायी आग

गया (आरएनएस)। बिहार में गया जिले के नक्सल प्रभावित डुमरिया प्रखंड के भदवर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने सडक़ निर्माण कार्य में लगी पोकलेन मशीन में आग लगा दी। पुलिस अधीक्षक (नगर) राकेश कुमार ने बुधवार को यहां बताया कि पिपरवार गांव के निकट सडक़ का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान मंगलवार की देर रात नक्सलियों ने धावा बोला और पेट्रोल छिडक़ कर एक पोकलेन मशीन में आग लगा दी। नक्सलियों ने घटनास्थल पर एक पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें लेवी की मांग की गयी है। श्री कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

महिला दिवस पर शख्स ने की पत्नी की हत्या

कोल्हापुर (आरएनएस)। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की करवीर तहसील के पचगांव में महिला दिवस पर एक व्यक्ति ने घरेलू कलह को लेकर अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से घरेलू मुद्दे को लेकर दंपति के बीच झगड़ा चल रहा था आज देर रात व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम अरुणा विजय पवार (28) है जो मूल रूप से कर्नाटक के बेलगाम जिले की रहने वाली थीं। सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही करवीर पुलिस मौके पर पहुंची और पति विजय को हिरासत में ले लिया।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को स्वीकृति दी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर के साथ गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम) की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। आयुष मंत्रालय के तहत जामनगर में डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम की स्थापना की जाएगी। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए प्रथम और एकमात्र आउटपोस्टिड वैश्विक केंद्र (कार्यालय) होगा।

लोकसभा अध्यक्ष 11 मार्च को एनवाईपीएफ के तीसरे संस्करण के समापन समारोह को करेंगे संबोधित

नईदिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिरला 11 मार्च को संसद के केन्द्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव (एनवाईपीएफ) के तीसरे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। केन्द्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज एनवाईपीएफ 2022 के राष्ट्रीय दौर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। शीर्ष तीन राष्ट्रीय विजेताओं को भी समापन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा।

ब्रिटेन ने की बड़ी कार्रवाई, रूसी विमान को अपने कब्जे में लिया- बढ़ सकता है तनाव

लंदन। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन ने एक रूसी प्लेन को कब्जे में ले लिया है। इससे तनाव और बढऩे की आशंका है। रूसी प्लेन को कब्जे में लेने की बात यूके के यातायात मंत्री ने बताई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर रूस के प्लेन या चार्टर्ड विमान उनके एयरस्पेस में घुसते हैं तो इसे क्राइम माना जाएगा और प्लेन को जब्त किया जाएगा। दरअसल, जंग के बाद रूसी विमानों को पहले से यूके में बैन कर दिया गया था, लेकिन अमीर रूसी नागरिकों ने दूसरे देशों में अपने चार्टर्ड प्लेन को रजिस्टर किया हुआ था जो यूके में पहुंच रहे थे। ऐसे विमानों को भी ब्रिटेन के ऊपर उड़ाने पर रोक लगा दी गई थी। कहा गया था कि ऐसी स्थिति में रूसी विमान को जब्त कर लिया जाएगा. अब ऐसा ही किया गया है।

मुख्यमंत्री ने किया 1 लाख 12 हजार 603 करोड़ का बजट पेश

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत करने के बाद प्रेसवार्ता में श्री बघेल ने कहा कि यह बजट राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की समृद्धि, गांवों की आर्थिक प्रगति, शिक्षा में गुणवत्ता एवं प्रगति के नवीन आयाम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण, महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास, युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के नवीन अवसरों के सृजन, शासकीय सेवकों के भविष्य को सुरक्षित करने, ग्रामीण एवं शहरी अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने तथा जनता के लिए संवेदनशील प्रशासन की भावना के साथ प्रदेश के लोगों को समर्पित है।

मुख्यमंत्री ने आर्थिक स्थिति पर कहा कि स्थिर दर पर वर्ष 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष 2021-22 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 11.54 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राष्ट्रीय स्तर पर 9.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में यह अधिक है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 3.88 प्रतिशत वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 प्रतिशत वृद्धि और सेवा क्षेत्र में 8.54 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित। कृषि एवं सेवा क्षेत्र में राज्य की अनुमानित वृद्धि दर, राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64 प्रतिशत अधिक है। प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में 3 लाख 52 हजार 161 करोड़ से बढक़र वर्ष 2021-22 में 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 प्रतिशत अधिक है। श्री बघेल ने प्रति व्यक्ति आय की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 1,05,778 की तुलना में वर्ष 2021-22

में प्रति व्यक्ति आय 1,18,401 रूपये है जो कि गत वर्ष की तुलना में 11.90 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित एवं 2022-23 का बजट अनुमान की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्ति के बजट अनुमान 97 हजार 145 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 99 हजार 601 करोड़ है। बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 2.52 प्रतिशत की वृद्धि। शुद्ध व्यय का बजट अनुमान 97 हजार 106 करोड़ से बढ़ाकर पुनरीक्षित अनुमान में 99 हजार 559 करोड़ प्रस्तावित। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्ति का बजट अनुमान 1 लाख 04 हजार करोड़ जो गत वर्ष की अनुमानित बजट प्राप्तियों से 7 प्रतिशत अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 44 हजार 500 करोड़, केन्द्र से प्राप्तियां 44 हजार 573 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 14 हजार 927 करोड़ अनुमानित। इस तरह वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग का आकार 1 लाख 12 हजार 603 करोड़ है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनप्र्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 1 लाख 04 हजार करोड़ अनुमानित। राजस्व व्यय 88 हजार 372 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 15 हजार 241 करोड़ है। पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14.6 प्रतिशत।

उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग में गैर-वन मद अंतर्गत वर्गीकृत नारंगी क्षेत्र में से 30 हजार 439 हेक्टेयर भूमि संयुक्त सर्वेक्षण उपरांत राजस्व मद में वापसी। नये उद्योगों की स्थापना, शासकीय भवनों के निर्माण, सडक़ एवं रेलमार्ग का विकास तथा अन्य गतिविधियों के लिये सरलता से भूमि की उपलब्धता।

उन्होंने बताया कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 6 हजार वार्षिक सहायता राशि को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 7 हजार प्रतिवर्ष किया गया है।

अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले मांझी, बैगा, गुनिया, पुजारी इत्यादि, जिनमें हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया भी शामिल हैं, को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ मिलेगा। गोठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित कर स्थानीय खाद्य उत्पाद एवं लघु वनोपज उत्पादों के मूल्य संवद्र्धन के लिये प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना। बांस एवं काष्ठ शिल्प, मेटल शिल्प तथा अन्य हस्त शिल्प से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिये स्थानीय युवाओं को सहयोग। उन्होंने बताया कि औद्योगिक पार्कों में तैयार उत्पादों का चयन हितधारकों के कौशल, उपलब्ध कच्चा माल, उपभोक्ताओं में मांग तथा परिवहन एवं आवागमन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना तथा बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड का गठन, मछली पालन एवं लाख उत्पादन को कृषि के समकक्ष दर्जा, मिलेट मिशन एवं वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से रोजगार के नये अवसरों का सृजन। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा विभिन्न स्थानीय उत्पादों की ब्रान्डिंग और विपणन छत्तीसगढ़ हर्बल्स के नाम से होगा। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रम का विभिन्न नवाचारी योजनाओं के साथ समन्वय एवं राज्य स्थित विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ लेते हुए नये रोजगार सृजन की संभावनाओं पर कार्य हेतु छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रपति कोविन्द ने भारतीय संस्कृति में मानवीय जिजीविषा पुस्तक की प्रथम प्रति प्राप्त की

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत के राष्ट्रपति, राम नाथ कोविन्द ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन भारतीय संस्कृति में मानवीय जिजीविषा की पहली प्रति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष एवं निबंध संकलन की संपादक डॉ अपर्णा द्विवेदी से प्राप्त की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी नूपुर पाण्डेय, रत्नेश मिश्र और अशोक महेश्वरी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

भारतीय परंपरा में आधुनिकता और आधुनिकता में परंपरा के अप्रतिम द्रष्टा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा विज्ञान, समालोचना, सांस्कृतिक विमर्श, उपन्यास तथा निबंध के क्षेत्र में नए मार्ग प्रशस्त किए। संत कबीर को महान साहित्यिक कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में उनके योगदान ने हमारी साहित्यिक विरासत को समृद्ध किया है।

इस अवसर पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में राष्ट्रपति ने कबीर जैसे कवियों के कृतित्व के प्रसार में आचार्य द्विवेदी के योगदान को सराहा। साथ ही उन्होंने जन-संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के प्रसार पर बल दिया।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के कर्मचारियों ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह की शोभा बढ़ाई

नईदिल्ली (आरएनएस)। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के कर्मचारियों ने कार्य-निष्पादन वर्ष 2018 के लिए प्रदान किये गए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (वीआरपी) के समारोह में अपनी प्रभावशाली छाप छोड़ी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे। भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर

औद्योगिक उपक्रमों के श्रमिकों के प्रयासों को पुरस्कृत करना है। कुल 96 पुरस्कार विजेताओं में से 52 पुरस्कार विजेता सेल से जुड़े हुए हैं, जो कुल विजेताओं का लगभग 54त्न हिस्सा है। सेल के कर्मचारियों ने कार्य-निष्पादन वर्ष 2018 के लिए दिए गए कुल 28 पुरस्कारों में से 11 पुरस्कार जीते हैं, जो कि विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में कुल पुरस्कारों का 39त्न भाग है।

सेल की अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल ने पुरस्कार विजेता कर्मचारियों को एक कार्यक्रम में अलग से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान विजेताओं को बधाई देते हुए श्रीमती मंडल ने जोर देकर कहा कि इतनी बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने से हमारे कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, समर्पण और उत्कृष्टता की पुष्टि हुई है। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रतिभाशाली कर्मचारी सेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संगठन की संस्कृति ने हमेशा भागीदारी, नवाचार तथा जुनून को प्रोत्साहित किया है। सेल ने हमेशा अपने कर्मचारियों को उनके अंदर छिपी प्रतिभा दिखाने की स्वतंत्रता उपलब्ध कराई है और उन्हें यह जानकर खुशी हो रही है कि इस तरह के एक उल्लेखनीय मंच पर इसे काफी पहचाना जा रहा है।

वैज्ञानिकों ने यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन के उत्पादन को विकसित किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय वैज्ञानिकों ने यूरिया के विद्युत अपघटन (इलेक्ट्रोलिसिस)की मदद से ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विद्युत उत्प्रेरक प्रणाली (इलेक्ट्रोकैटलिस्ट सिस्टम) को तैयार किया है। यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस कम लागत वाले हाइड्रोजन उत्पादन के साथ यूरिया आधारित अपशिष्ट उपचार की दिशा में सहायक है। हमारे देश के लाभ के लिए ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा जल के विद्युत अपघटन (इलेक्ट्रोलिसिस) के माध्यम से होने वाले हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को 70त्न तक कम किया जा सकता है।

जल विखंडन के ऊर्जा-गहन अंश तथा ऑक्सीजन की उत्पत्ति के स्थान पर यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में यूरिया का ऑक्सीकरण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए कम लागत वाले

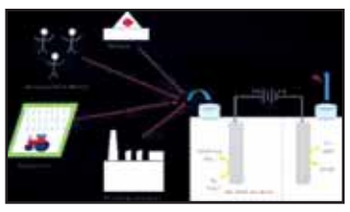

पृथ्वी-प्रचुर मात्रा में निकल (एनआई) -आधारित उत्प्रेरक का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यूरिया ऑक्सीकरण से जुड़ी मुख्य चुनौती उत्प्रेरक की लंबी क्रिया अवधि को बनाए रखना है क्योंकि सक्रिय साइट पर प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती (सीओएक्स) का अत्यधिक अवशोषण, जिसे उत्प्रेरक विषाक्तता कहा जाता है, परस्पर क्रिया में हानि का कारण बनता है।

इस दिशा में, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान, नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र (सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज -सीईएनएस) से एलेक्स सी, गौरव शुक्ला, मोहम्मद सफीर एनके, और डॉ नीना एस जॉन, सरकार भारत सरकार ने यूरिया के इलेक्ट्रो-ऑक्सीकरण से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए निकल ऑक्साइड (एनआईओएक्स) आधारित प्रणाली विकसित की है।

पत्रिका (जर्नल) इलेक्ट्रोचिमिका एक्टा और जर्नल ऑफ मैटेरियल्स केमिस्ट्री ए में प्रकाशित शोध कार्यों की श्रृंखला में, वैज्ञानिकों ने विद्युत उत्प्रेरकों (इलेक्ट्रोकैटलिस्ट्स) की खोज की है और यह दिखाया है कि सतह के दोषपूर्ण निकेल ऑक्साइड (एनआईओ) और डाईनिकेल ट्राईऑक्साइड एनआई2ओ 3 प्रणाली जिनमें अधिक एनआई3 आयन होते हैं, पारंपरिक एनआईओ की तुलना में अधिक कुशल इलेक्ट्रोकैटलिस्ट हैं। उन्होंने एनआईओ (ई-एनआईओ) में सतह दोषपूर्ण असंतृप्त निकेल (एनआई) साइटों का उत्पादन करने के लिए उच्च-ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग किया है। अध्ययन से पता चलता है कि ई-एनआईओ यूरिया अणु के सुदृढ़ अवशोषण के कारण यूरिया इलेक्ट्रो-ऑक्सीकरण की प्रत्यक्ष व्यवस्था को पसंद करता है, जबकि एनआईओ कम क्रिया के साथ अप्रत्यक्ष तंत्र का पक्षधर है। इसके अलावा, प्रमुख इलेक्ट्रोकैटलिस्ट विष सीओएक्स को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड (केओएच) और यूरिया के आणविक अनुपात को बेहतर गतिज (काईनेटिक्स) के साथ समायोजित करके हटाया जा सकता है। शोधकर्ताओं, एलेक्स और गौरव, की राय है कि ई-बीम उपचार विद्युत उत्प्रेरकों (इलेक्ट्रोकैटलिस्ट्स) पर बड़ी मात्रा में समन्वित रूप से असंतृप्त सक्रिय साइटों का उत्पादन करने का एक प्रभावी तरीका है। यह देखा गया कि ये उत्पन्न साइटें यूरिया को प्रभावी ढंग से सोख लेती हैं और प्रत्यक्ष यूरिया इलेक्ट्रो-ऑक्सीडेशन तंत्र (यूओआर) का पक्ष लेती हैं।

भारत के 23 नाविकों को मायकोलाइव पोर्ट से निकाला गया

कीव । यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा कि मायकोलाइव पोर्ट में फंसे शेष 23 भारतीय नाविकों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया और उन्हें बुखारेस्ट के रास्ते लाया जा रहा है। दूतावास ने ट्वीट किया,शेष 23 नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वे मोल्दोवा सीमा पार कर चुके हैं और बुखारेस्ट की ओर जा रहे हैं।

ये सभी 23 भारतीय नाविक उन 75 भारतीय नाविकों के समूह का हिस्सा हैं, जो दक्षिणी यूक्रेन के मायकोलाइव पोर्ट में फंसे हुए थे। जिनमें से मंगलवार को 52 नाविक निकाले गये थे। उनके साथ दो लेबनानी और तीन सीरियाई नाविकों को भी बाहर निकाला गया था तथा शेष बचे 23 नाविक वहीं रहे गए थे।

इससे पहले मंगलवार को, कीव में भारतीय दूतावास ने कहा कि उसने मायकोलाइव पोर्ट में फंसे 75 भारतीय नाविकों को निकालने के लिए हस्तक्षेप किया है लेकिन कुछ समस्याओं के कारण 23 नाविकों को निकाला नहीं जा सका, जिन्हें निकालने के लिए अगले दिन प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन में 24 फरवरी को शुरू हुए सैन्य कार्रवाई के बाद ये सभी नाविक अपने जहाज में फंसे थे।

किसानों को बीज से बाजार तक सुविधाएं दे रही है सरकार : चौधरी

केन्द्रीय मंत्री ने किया पूसा कृषि विज्ञान मेला-2022 का शुभारंभ

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याणमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित तीन दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया। डेयर के सचिव व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रने अध्यक्षता की। इस अवसर पर, चौधरी ने दो एकड़ क्षेत्र में विकसित पूसा एग्री कृषि हाट परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। मेले में देश के विभिन्न

भागों से पधारे हजारों प्रगतिशील किसान, महिला उद्यमी व स्टार्ट-अप्स शामिल हुए हैं।

समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी ने पूसा संस्थान द्वारा किसान हितों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए किसानों से नई तकनीकों, वैज्ञानिक नवाचारों का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा किसान हितों के लिए किए जा रहे कार्यों व कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार किसानों को बीज से बाजार तक की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। किसानों की मेहनत व वैज्ञानिकों के अनुसंधान की बदौलत भारतीय कृषि उन्नत हो रही है। युवाओं में कृषि के प्रति उत्साह जागृत हो रहा है, जिससे उन्हें रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय के बजट को लगातार बढ़ाया है, जो अब 1.32 लाख करोड़ रुपये है जबकि सात साल पहले मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले यह बजट मात्र लगभग 23 हजार करोड़ रु. था। वर्तमान बजट में से आधी से ज्यादा राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में सीधे किसानों के बैंक खातों में दी जा रही है, इससे सरकार ने किसानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता जाहिर की है, वहीं स्वामीनाथन समिति की सभी सिफारिशों को मोदी की सरकार ने लागू किया है।

चौधरी ने कहा कि सरकार ने न केवल एमएसपी को ज्यादा फसलों पर दर बढ़ाकर लागू किया बल्कि खरीद भी बढ़ाई है। देश में 10 हजार नए एफपीओ 6,865 करोड़ रु. खर्च करके बनाए जा रहे हैं। एक लाख करोड़ रु. के कृषि इंफ्रा फंड से गांव-गांव सुविधाएं जुटाई जा रही है। कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए भी विशेष पैकेज दिए गए हैं। किसानों की मेहनत व सरकार के प्रयासों से दलहन सहित खाद्यान्न उत्पादन में रेकार्ड वृद्धि हुई है। ये सारे प्रयास दर्शाते है कि सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने किसानों से सरकार के साथ मिल-जुलकर, योजनाओं का लाभ उठाते हुए आगे बढऩे का आह्वान किया।

समारोह में, उप-महानिदेशक (कृषि प्रसार) डॉ ए.के. सिंह, उपमहानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ. टी.आर. शर्मा, एपीडा के चेयरमैन डॉ. एम. अंगमुथु भी विशेष रूप से उपस्थित थे।

आज लोकार्पित पूसा एग्री कृषि हाट परिसर में किसान तथा किसान उत्पादक संगठन अपने उत्पादों का प्रत्यक्ष विपणन कर पाएंगे। इस सुविधा से उपभोक्ता सीधे ही किसानों के उत्पाद खरीद पाएंगे, जिससे इन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिल सकेगी। कृषक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस विशाल परिसर में 60 स्टाल, हाट, एवं दुकानों का प्रावधान है।

आईएआरआई के निदेशक डॉ. अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष 9 से 11 मार्च तक आयोजित इस मेले का मुख्य विषय तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान है। मेले के प्रमुख आकर्षण हैं: स्मार्ट/डिजिटल कृषि, एग्री स्टार्टअप एवं किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), जैविक तथा प्राकृतिक खेती, संरक्षित खेती/ हाइड्रोपोनिक/ एरोपोनिक/ वर्टिकल खेती, कृषि उत्पादों के निर्यात, प्रोत्साहन सलाह केंद्र।